संक्षिप्त समाचार

मातृभाषा का महत्व विषय पर परिचर्चा आयोजित

(संवाददाता) विकासनगर। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में मातृभाषा दिवस के उपलक्ष में 'मातृभाषा का महत्व' विषय पर एक परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रो. राधेश्याम गंगवार, प्रो. आशुतोष त्रिपाठी व छात्र–छात्राओं ने अपने विचार रखे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. गोविंदराम सेमवाल ने मातृभाषा को जन्मभूमि की भाषा बताते हुए देश की संस्कृति की रक्षा करने में उसके महत्व पर प्रकाश डाला।

चिंताहरण मंदिर में भंडारा आयोजित

(संवाददाता) विकासनगर। छावनी बाजार चकराता स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर में आयोजित विशाल भंडारे में छावनी बाजार सहित आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर विशेष आरती की गई। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के समक्ष मत्था टेक आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। इसके पश्चात दोपहर को भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

स्काउट गाइड के जन्मदाता को याद किया गया

(संवाददाता) विकासनगर। केंद्रीय तिब्बती विद्यालय हरबर्टपुर में स्काउट गाइड के जन्मदाता लार्ड वेडेन पावेल और लेडी वेडेन पावेल का जन्मदिन चिंतन दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। चिंतन दिवस का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य डा. एपी सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने स्काउट गाइड व सभी छात्र–छात्राओं को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित किया।

शक्तिनहर में धक्का देने का आरोपी गिरफ्तार

(संवाददाता) विकासनगर। जान से मारने की नीयत से एक व्यक्ति को शक्ति नहर में धकेल देने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को मानसिंह पुत्र स्व. चरण सिंह निवासी गली नंबर 4 वार्ड नंबर 5 आसन बाग हरबर्टपुर द्वारा थाना विकासनगर पर तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति धीर सिंह निवासी भीमावाला थाना विकासनगर द्वारा 19 फरवरी की रात्रि करीब 8 बजे उसे पूजा–पाठ कराने के बहाने धौलातप्पड़ कुल्हाल में शक्ति नहर के पास बुलाया तथा उसे जान से मारने की नीयत से शक्ति नहर में धकेल दिया।

बस अड्डे एवं वर्कशाप का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश

बैठक

■ एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कराकर मामले का निस्तारण करें

देहरादून। **सवांददाता**

राज्यममंत्री धन सिंह श्रीनगर बस अड्डे के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय स्थित सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर, गढ़वाल में प्रस्तावित बस अड्डे के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण एवं बस अड्डे के निर्माण संबंधी समीक्षा बैठक ली। बैठक में डॉ. रावत द्वारा आवास, शहरी विकास तथा परिवहन निगम के अधिकारियों को तत्काल बस अड्डे एवं वर्कशाप का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कराकर मामले का निस्तारण करें।

सचिव आवास नितेश झा ने अवगत कराया कि विभाग के पास पार्किंग हेतु 15 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं जिससे श्रीनगर गढ़वाल में बस अड्डा एवं पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र नयी डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सचिव परिवहन एवं शहरी विकास शैलेश बगोली ने बताया कि जिन जिन स्थानों पर परिवहन निगम के पास अपनी भूमि उपलब्ध है वहां पर बस अड्डे के साथ बहुमंजिला पार्किंग की योजना है, जिस के लिए धनराशि आवास विभाग एवं शहरी विकास विभाग मिलकर उपलब्ध करायेंगे। डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर गढ़वाल में प्रस्तावित बस अड्डा चार धाम यात्रा के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है जिसके निर्माण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा के मामलों को भी स्थायी लोक अदालत में सम्मिलित किया गया

(संवाददाता) देहरादून। स्थायी लोक अदालत देहरादून में जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों में जिनका मूल्यांकन एक करोड़ तक है, को आपसी विचार–विमर्श, समझौते व गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाता है। जन उपयोगी सेवाओं में वायु, सड़क व जलमार्ग यात्रियों व माल वहन के लिए यातायात सेवा, डाक, तार व टेलीफोन सेवा, विद्युत, जल व प्रकाश, लोक सफाई व स्वच्छता प्रणाली सेवा, अस्पताल औषाधालय सेवा, बीमा सेवा, शैक्षिक व शैक्षणिक संस्थान, आवास और भू–सम्पदा सेवा शामिल है। उत्तराखण्ड शासन न्याय विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा को सम्मिलित कर दिया गया है।

कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर लगी मुहर

फैसले

मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिली

3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है: कौशिक

संवाददाता

देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लग गई है। बैठक में मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिल गई। राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी दी गई, युवा आयोग भी राज्य योजना आयोग में शामिल होगा। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। दुकानों का आवंटन लॉटरी से होगा। 3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। दुकानों का आवंटन डीएम करेंगे। बार का तीन साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। राज्पाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण को लेकर समिति का गठन होगा।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समिति के अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य विभाग की दो नियमवली को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी दी गई, युवा आयोग राज्य योजना आयोग में शामिल होगा। उत्तराखंड नदी तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने पर सहमति बनी है। परिवहन के ढांचे में बदलाव करते हुए विभाग में 116 नए पदों को मंजूरी प्रदान की गई।

हरिद्वार में एक धर्मशाला का लैंड यूज आवासीय करने पर सहमति प्रदान की गई। गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे, प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व इसके सदस्य होंगे। 53,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट होगा। यह पहले से 10 प्रतिशत ज्यादा होगा। आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जहां चाहे वहां मधनिषेध को बंद कर सकती है। मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी प्रदान की गई।

अन्य फैसले

- नई आबकारी नीति को मंजूरी, उत्तर प्रदेश से कम की मदिरा की दर। बार का लाइसेंस अब देंगे डीएम।
- जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण को कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता कमेटी बनी।
- नर्सों की भर्ती को नियमावली मंजूर।
- राज्य योजना आयोग में 126 पदों का सृजन।
- परिवहन विभाग की ढांचे को मंजूरी सभी जिलों में संभागीय परिवहन अधिकारी के पद रहेंगे
- गैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री रहेंगे।
- मेक इन इंडिया के तहत उत्तराखंड में रक्षा उपकरण और एयरो स्पेस के उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन बनाने से जुड़े उद्योगों को हरी झंडी।

17 विधायक अब तक अपनी आधी विधायक निधि भी खर्च नहीं कर पाए

(संवाददाता) देहरादून। उत्तराखंड के अधिकतर विधायक अपनी निधि खर्च करने में पीछे चल रहे हैं। 71 विधायकों (एक नामित विधायक) में से 17 ऐसे हैं, जो अब तक अपनी आधी विधायक निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। खर्च के मामले में धारचूला विधायक हरीश धामी सबसे पीछे और हरिद्वार ग्रामीण के विधायक यतीश्वरानंद सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 70 फीसद धनराशि खर्च कर चुके हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष और हल्द्वानी विधायक इंदिरा हृदयेश 66 फीसद निधि खर्च कर चुकी हैं। विधायक निधि के खर्च की तस्वीर आरटीआइ कार्यकर्ता अधिवक्ता नदीम उद्दीन की ओर से मांगी गई जानकारी में सामने आई। वर्ष 2017–18 और 2019–20 (दिसंबर तक) में उत्तराखंड के 71 विधायकों को 798.75 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई। इसमें से अब तक 481.16 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। यानी सभी विधायकों की औसतन 40 फीसद निधि खर्च होनी शेष हैं। हालांकि, विधायक निधि खर्च करने के मामले में 2017–18 की अपेक्षा 2019–20 में सुधार देखने को मिला है। दिसंबर 2017 तक 195.25 करोड़ रुपये के सापेक्ष सिर्फ 12 फीसद (23.29) करोड़ रुपये खर्च किए जा सके थे। इसके बाद निधि जारी करने की राशि बढने के साथ खर्च की रफ्तार भी बढ़ी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०-
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।